MODEL ANSWER

Q. Analyze the impact of reciprocal tariffs in international trade. How do such policies influence global trade dynamics and economic relations between nations?

Reciprocal tariffs are a trade mechanism where a country imposes the same level of tariffs on imports as its trading partner levies on its exports. The U.S., under the Trump administration, has revived this policy to address perceived trade imbalances. While the objective is to create a "fair" trading system, the policy could have significant ramifications for global trade, particularly for countries like India. Given that India has a $38 billion trade surplus with the U.S., the introduction of reciprocal tariffs could make Indian exports costlier and alter trade dynamics between the two nations.

The **reciprocal tariff system** aims to match tariff rates between trading partners to ensure uniformity in trade policies. Under this system, the **U.S. will impose the same level of tariffs on imports as India applies to U.S. goods**, effectively neutralizing any advantage India previously enjoyed. Additionally, export incentives, tax breaks, and subsidies provided by countries like India will be considered while determining the final tariff rate. This move also aims to **eliminate differential treatment**, ensuring that developing nations, including India, no longer receive tariff relaxations that were previously granted under WTO rules.

Impact of Reciprocal Tariffs on India

1. Effect on Indian Exports

- **Increased Cost of Indian Goods in the U.S.:** Sectors like textiles, pharmaceuticals, and automobiles which are India's key exports could face **higher tariff barriers**, reducing their competitiveness.
- **Trade Deficit Adjustments:** To balance trade, India may have to increase imports from the U.S., especially in sectors like **defense, oil, and gas**.
- **Weakening of the Rupee:** Higher U.S. imports could increase demand for the **dollar**, leading to rupee depreciation and making imports costlier for India.

2. Impact on Indian Industries

- **Pressure on MSMEs (Micro, Small & Medium Enterprises):** Many small Indian businesses rely on exports to the U.S. Higher tariffs will make it difficult for them to compete, especially in **pharmaceuticals and textile manufacturing**.
- **Effect on Atmanirbhar Bharat:** India's self-reliance initiative could slow down if reciprocal tariffs force India to purchase more **American-made products**.

3. Potential Shift in Foreign Investments

- **Increase in FDI:** To avoid high tariffs, U.S. companies might **set up local manufacturing** in India, leading to greater **Foreign Direct Investment (FDI)**.
- **Strategic Trade Negotiations:** India could renegotiate trade agreements to secure better terms, similar to the **India-UAE CEPA (2022)**, which eased trade barriers.

However, the rise of protectionism is not unique to U.S.-India trade relations. According to the World Trade Organization (WTO), trade restrictions imposed by G20 economies in 2023 affected $1.6 trillion worth of global trade. Similarly, the IMF (2022) estimated that trade wars led to a 0.4% decline in global GDP, hitting developing nations the hardest.

The U.S.'s reciprocal tariff policy, aimed at ensuring balanced trade, poses significant challenges for India's export-driven industries. Higher tariffs on Indian goods could reduce trade competitiveness, impact key sectors like textiles, pharmaceuticals, and automobiles, and alter the Indo-U.S. trade

equation. Additionally, the elimination of differential treatment for developing economies under WTO norms may further constrain India's trade advantages. To counter these challenges, India needs a strategic approach that balances trade relations while safeguarding its economic interests.

To mitigate the adverse effects, India must strengthen its position in global trade negotiations, ensuring that developing nations continue to have a fair playing field. Expanding trade partnerships with ASEAN, the EU, and Africa, boosting domestic manufacturing of high-value products like semiconductors and electronics, and securing sector-specific trade agreements—similar to the India-UAE CEPA—can provide stability. A well-rounded strategy focused on diversification, self-reliance, and diplomatic engagement will help India navigate the evolving global trade landscape while maintaining a stable and mutually beneficial relationship with the U.S.

Samyak
An Institute For Civil Services

प्रश्न. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पारस्परिक टैरिफ के प्रभाव का विश्लेषण करें। ऐसी नीतियाँ वैश्विक व्यापार गतिशीलता और राष्ट्रों के बीच आर्थिक संबंधों को कैसे प्रभावित करती हैं?

पारस्परिक टैरिफ एक व्यापारिक व्यवस्था है, जिसमें कोई देश अपने आयात पर उसी स्तर का शुल्क लगाता है, जैसा कि उसका व्यापारिक भागीदार अपने निर्यात पर लागू करता है। ट्रंप प्रशासन के तहत, अमेरिका ने कथित व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए इस नीति को पुनः लागू किया है। इसका उद्देश्य एक "निष्पक्ष" व्यापार प्रणाली स्थापित करना है, लेकिन यह नीति वैश्विक व्यापार पर, विशेष रूप से भारत जैसे देशों पर, महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। भारत का अमेरिका के साथ 38 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष होने के कारण, पारस्परिक टैरिफ की शुरुआत भारतीय निर्यात को महंगा बना सकती है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है।

पारस्परिक टैरिफ प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यापारिक भागीदारों के बीच शुल्क दरों में समानता हो, ताकि व्यापार नीतियों में एकरूपता बनी रहे। इस प्रणाली के तहत, अमेरिका अपने आयात पर वही शुल्क लगाएगा, जो भारत अमेरिकी वस्तुओं पर लागू करता है, जिससे भारत को पहले प्राप्त किसी भी लाभ का असर समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, अंतिम शुल्क दर निर्धारित करते समय भारत जैसे देशों द्वारा दी जाने वाली निर्यात प्रोत्साहन, कर छूट और सब्सिडियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस कदम का उद्देश्य भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि अब भारत जैसे विकासशील देशों को वह टैरिफ छूट नहीं मिलेगी, जो पहले विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के तहत दी जाती थी।

पारस्परिक टैरिफ का भारत पर प्रभाव

1. **भारतीय निर्यात पर प्रभाव**
    - **अमेरिका में भारतीय वस्तुओं की बढ़ी हुई लागत:** भारत के प्रमुख निर्यात जैसे वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल को उच्च टैरिफ दरों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता घट सकती है।
    - **व्यापार घाटे का समायोजन:** व्यापार असंतुलन को संतुलित करने हेतु, भारत को अमेरिका से आयात बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है, विशेष रूप से रक्षा, तेल और गैस जैसे क्षेत्रों में।
    - **रुपये का कमजोर होना:** अमेरिका से बढ़ते आयात से डॉलर की मांग बढ़ सकती है, जिससे रुपये का मूल्यह्रास होगा और भारत के लिए आयात महंगा हो जाएगा।
2. **भारतीय उद्योगों पर प्रभाव**
    - **एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) पर दबाव:** कई छोटे भारतीय व्यवसाय अमेरिका के निर्यात पर निर्भर रहते हैं। उच्च टैरिफ उनके लिए प्रतिस्पर्धा को कठिन बना सकते हैं, खासकर फार्मास्यूटिकल्स और वस्त्र उद्योग संबंधी क्षेत्र में।
    - **आत्मनिर्भर भारत पर प्रभाव:** यदि पारस्परिक टैरिफ भारत को अधिक अमेरिकी निर्मित उत्पादों का आयात करने के लिए मजबूर करते हैं, तो भारत की आत्मनिर्भरता संबंधी पहल की गति धीमी हो सकती है।
3. **विदेशी निवेश में संभावित बदलाव**
    - **एफडीआई में वृद्धि:** उच्च टैरिफ से बचने के लिए, अमेरिकी कंपनियां भारत में स्थानीय विनिर्माण स्थापित कर सकती हैं, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि हो सकती है।
    - **रणनीतिक व्यापार वार्ता:** भारत व्यापार समझौतों पर पुनः बातचीत कर सकता है ताकि बेहतर स्थिति को सुनिश्चित की जा सकें, जैसे कि भारत-यूएई सीईपीए (2022) ने व्यापार बाधाओं को कम किया।

हालाँकि, संरक्षणवाद का उदय केवल अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों तक सीमित नहीं है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अनुसार, 2023 में G20 देशों द्वारा लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों ने 1.6 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया। इसी तरह, IMF (2022) ने अनुमान लगाया कि व्यापार संबंधी युद्धों के कारण वैश्विक GDP में 0.4% की गिरावट आई, जिसका सबसे अधिक प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ा है।

अमेरिका की पारस्परिक टैरिफ नीति, जो संतुलित व्यापार सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखती है, भारत के निर्यात-आधारित उद्योगों के लिए गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न करती है। भारतीय वस्तुओं पर उच्च टैरिफ व्यापार प्रतिस्पर्धा को घटा सकते हैं, खासकर वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं और भारत-अमेरिका

व्यापार समीकरण को बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, WTO मानदंडों के तहत विकासशील देशों के लिए विभेदक उपचार को समाप्त करने से भारत के व्यापार संबंधी लाभ और भी कम हो सकते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारत को एक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो अपने आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए व्यापार संबंधों को संतुलित कर सके।

प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए, भारत को वैश्विक व्यापार वार्ता में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकासशील देशों को उचित अवसर मिलते रहें। आसियान, यूरोपीय संघ और अफ्रीका के साथ व्यापार साझेदारी का विस्तार करना, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को सुरक्षित करना - जैसे भारत-यूएई सीईपीए - स्थिरता प्रदान कर सकता है। विविधीकरण, आत्मनिर्भरता और कूटनीतिक संबंधों पर आधारित एक सशक्त रणनीति भारत को अमेरिका के साथ स्थिर और पारस्परिक लाभकारी संबंध बनाए रखने में मदद करेगी।

Samyak
An Institute For Civil Services